विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों और न्यायाधीशों के रिक्त पदों को दर्शित करने वाली सारणी।

क्र० सं०	न्यायालय का नाम	31.12.96 को लम्बित मामलों की सं०	1.3.1997 को न्यायाधीशों के रिक्त पद
	उच्चतम न्यायालय	6,660	5
	ग्रहण किए जाने वाले मामले		
	निपटाए जाने वाले मामले	16,856	
	उच्च न्यायालय		
1.	इलाहाबाद	7,88,448‡	5
2.	आन्ध्र प्रदेश	1,35,621	2
3.	मुंबई	2,29,927**	12
4.	कलकत्ता	2,64,312	12
5.	दिल्ली	1,45,905*	3
6.	गुवाहाटी	32,829	3
7.	गुजरात	1,39,821	4
8.	हिमाचल प्रदेश	18,530	शून्य
9.	जम्मू-कश्मीर	98,420**	2
10.	कर्नाटक	1,50,965	4
11.	केरल	2,17,823	2
12.	मध्य प्रदेश	75,616	6
13.	मद्रास	3,06,966**	2
14.	उड़ीसा	66,820	2
15.	पटना	96,345**	5
16.	पंजाब और हरियाणा	1,66,871**	4
17.	राजस्थान	95,368‡‡	शून्य
18.	सिक्किम	82*	2

‡ 30.6.1995 को यथाविद्यमान

* 30.6.1996 को यथाविद्यमान

** 30.9.1996 को यथाविद्यमान

‡‡ 30.12.1996 को यथाविद्यमान

Development of Ajanta, Ellora Complex

*230. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) the details of phased programmes Government have planned/undertaken/ completed to fully develop Ajanta, Ellora Complex;

(b) the details of the expenditure to be incurred in this regard;

(c) whether any foreign aid has since been received; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF TOURISM (SHRI SRIKANTA JENA): (a) to (d) The Government has entered into a Loan Agreement with the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) in January, 1992 for Conservation and Development of Ajanta & Ellora in Maharashtra. The OECF fund assistance for the Ajanta & Ellora project is to the tune of 3745 million Japanese Yen. The Project period is upto January, 1999. The major components of the project are aforestation, upgradation of Aerodrome facilities at Aurangabad, strengthening and improvement of roads, augmentation of water supply and sewerage, improvement of electricity supply, conservation of monuments and visitors management facilities. The OECF fund loan is not available in advance, the

implementing agencies i.e. State Government have to first incur expenditure from their own resources and then claim reimbursement from the OECF. Rs. 18.90 crores have been reimbursed by OECF till March 1996.

Incentive/Concessions in Excise Duty on Excess Production

*231. DR. Y. LAKSHMI PRASAD:
SHRI K.M. SAIFULLAH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce incentive/concessions in excise duty on excess peoduction to enable goods at cheaper rates for export without losing out on revenue; and

(b) if so, the measures likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) No, Sir. Under the Excise and Customs Laws, export goods or the materials used in the manufacture of export goods do not bear the incidence of excise or customs duties.

Operation of S.S.R Radars

*232. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as and when the S.S.R. Radars are operational, they will not be able to perform their full functions unless the corresponding equipment is installed on all aircraft operating within or airspace; and

(b) if so, what steps are being taken in this regard?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) Yes, Sir.

(b) All aircraft with Air India and most of the aircraft with Indian Airlines are already equipped with S-mode transponders. The remaining aircraft of Indian Airlines will be equipped by 30.6.1997. Two private airlines, namely Jet Airways and Modiluft have all their aircraft equipped with S-mode transponders and others have been directed by the Director general of Civil Aviation to complete the installation of this equipment by 31-3-1997.

उत्तर प्रदेश में गढ़वाल / कुमायुं संभागों में राष्ट्रीयकृत / निजी बैंकों की शाखाएं

*233. **श्री मनोहर कांत ध्यानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमायुं संभागों के पर्यवतीय क्षेत्रों में सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में 15 से 25 गांवों के लिए बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों की शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शाखाओं में ऋण-जमा अनुपात क्या है;

(ग) इन दो संभागों में कितनी शाखाएं खोलने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ऐसी विषम भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि 1994-95 की योजना अवधि के लिए प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या कवरेज जैसे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसाकि विगत में देश के शाखा नेटवर्क के विकास को दृष्टिगत करते हुए किया जाता था और शाखा विस्तार कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 1985-90 की अवधि के अन्त तक ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति-बैंक कार्यालय (एपीपीबीओ) औसत जनसंख्या में कमी आई है और यह 13000 हो गया है। तथापि, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की योजना के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अभी भी अतिरिक्त ग्रामीण शाखाएं खोलने की आवश्यकता है और / या कुछ विद्यमान ग्रामीण शाखाओं के कारोबार में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यह भी महसूस किया गया था कि पर्वतीय / जनजातीय क्षेत्रों और दूर-दराज के कम आबादी वाले क्षेत्रों में कुछ अतिरिक्त शाखाएं खोली जानी चाहिए ताकि ऐसे क्षेत्रों की बैंकिंग आवश्यकताएं